सेमीकंडक्टर मिशन से भारत बनेगा आत्मनिर्भर

डिजिटल संप्रभुता और चिप निर्माण में बड़ा कदम

स्वदेशी GPU विकास अगले 5 वर्षों में संभव

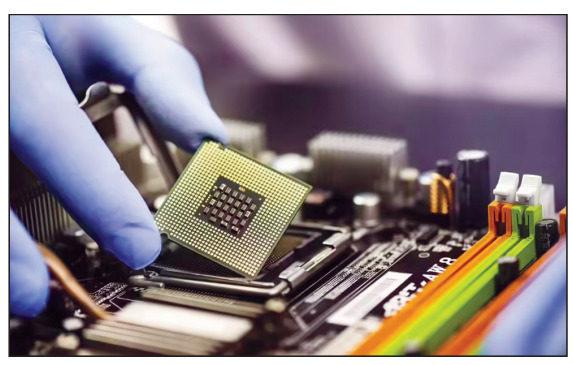

नई दिल्ली, 3 अगस्त. देश का सेमीकंडक्टर मिशन भारत को डिजिटल संप्रभुता की ओर ले जाएगा और चिप्स के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल करने में मदद करेगा.

विशेषज्ञों का कहना है कि यह पहल सीसीटीवी कैमरों, मोबाइल नेटवर्क, सैटेलाइट, कारों और स्मार्ट उपकरणों सहित कई अनुप्रयोगों में उपयोग होने वाली चिप्स के लिए देश को आत्मनिर्भर बनाएगी.

उद्योग निकाय एसोचैम के नेशनल काउंसिल ऑन डेटासेंटर के अध्यक्ष सुनील गुप्ता ने सॉवरेन टेक फॉर इंडियाज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कार्यक्रम में बताया कि डिजिटल संप्रभुता चिप स्तर से शुरू होती है. सरकार इस पूरे डिजिटल टेक्नोलॉजी स्टैक को समझती है, जिसमें चिप निर्माण से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और क्लाउड एप्लिकेशन तक सब कुछ शामिल है.

गुप्ता ने कहा कि चिप्स आधार बनाते हैं, जिससे उपकरण, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटासेट और अंतत: एप्लिकेशन विकसित होते हैं. उन्होंने कहा कि सरकार ने एक सेमीकंडक्टर मिशन बनाया है ताकि भारत अपने चिप्स को खुद ही डिजाइन, फैब्रिकेट, असेंबल और पैकेज कर सके.

उत्तर प्रदेश में बनेगी नई इकाई

भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत, उत्तर प्रदेश में एक और सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने को मंजूरी दी गई है. यह संयंत्र एचसीएल और फॉक्सकॉन का एक संयुक्त उद्यम होगा. यह संयंत्र मोबाइल फोन, लैपटॉप, ऑटोमोबाइल और अन्य उपकरणों के लिए डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स का निर्माण करेगा. इसकी मासिक उत्पादन क्षमता 20,000 वेफर्स और 3.6 करोड़ यूनिट होगी.

गुप्ता ने विश्वास व्यक्त किया कि मिशन की शुरुआत 28 नैनोमीटर चिप्स के साथ हुई है, लेकिन आने वाले समय में भारत दो और तीन नैनोमीटर जैसे सबसे उच्च-स्तरीय चिप्स का भी निर्माण करेगा. उन्होंने बताया कि आईटी मंत्री ने घोषणा की है कि अगले पांच वर्षों में भारत अपना स्वदेशी जीपीयू भी विकसित कर सकता है.

दुर्लभ पृथ्वी धातु पर भी जोर

गुप्ता ने चीन द्वारा निर्यात प्रतिबंधों के बीच दुर्लभ पृथ्वी धातुओं के स्रोतों को व्यापक बनाने के भारत के प्रयासों पर भी बात की. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की हालिया लैटिन अमेरिका और अफ्रीका यात्राएं इस दिशा में महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निर्माण में इन धातुओं का उपयोग होता है और सरकार इस पहलू को लेकर भी गंभीर है. भारत क्लाउड की सह-संस्थापक दिपाली पिल्लई ने डिजिटल इंडिया के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि आर्थिक और सुरक्षा दोनों के लिए सब कुछ देश में होना बहुत महत्वपूर्ण है.

35 जरूरी दवाओं की कीमत तय

सरकार के फैसले से इलाज अब और सस्ता होगा

एनपीपीए ने दवाओं की खुदरा कीमतें कीं तय

नई दिल्ली, 3 अगस्त. केंद्र सरकार ने जनता को बड़ी राहत देते हुए 35 आवश्यक दवाओं की खुदरा कीमतें तय कर दी हैं. रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी एक विस्तृत आदेश के अनुसार, इन दवाओं का अब एक निश्चित मूल्य होगा, जिससे आम आदमी के लिए इलाज और अधिक सस्ता हो जाएगा.

यह कदम राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा कीमतों को नियंत्रित कर आवश्यक दवाओं तक किफायती पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है.

यह निर्णय दवा आदेश, 2013 के प्रावधानों के तहत लिया गया है. इस मूल्य नियंत्रण आदेश में कई चिकित्सीय श्रेणियों की दवाएं शामिल हैं, जिनमें एंटी-इंफ्लेमेटरी, कार्डियोवैस्कुलर, एंटीबायोटिक, एंटी-डायबिटिक और मनोरोग संबंधी दवाएं प्रमुख हैं.

जिन प्रमुख दवाओं की कीमतें तय की गई हैं, उनमें एसिक्लोफेनाक, पैरासिटामोल और ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन का निश्चित खुराक संयोजन, एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लावुलानेट, एटोरवास्टैटिन संयोजन और एम्पाग्लिफ्लोजिन, सिटाग्लिप्टिन और मेटफॉर्मिन जैसे नए ओरल एंटी-डायबिटिक संयोजन शामिल हैं.

दवाओं की नई कीमतें

डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज द्वारा विपणन किए जाने वाले एसिक्लोफेनाक-पैरासिटामोल-ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन टैबलेट की कीमत अब 13 रुपये तय की गई है, जबकि इसी तरह की कैडिला फार्मास्यूटिकल्स द्वारा विपणन की जाने वाली दवा की कीमत 15 .01 रुपये होगी. हृदय रोगों के लिए व्यापक रूप से उपयोग होने वाले एटोरवास्टैटिन 40 एमजी और क्लोपिडोग्रेल 75 एमजी वाले एक टैबलेट की कीमत 25 .61 रुपये होगी. बैक्टीरियल संक्रमण के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लावुलानेट ओरल सस्पेंशन (जैडस हेल्थकेयर) की 1 मिलीलीटर की कीमत 3 .32 रुपये तय की गई है.

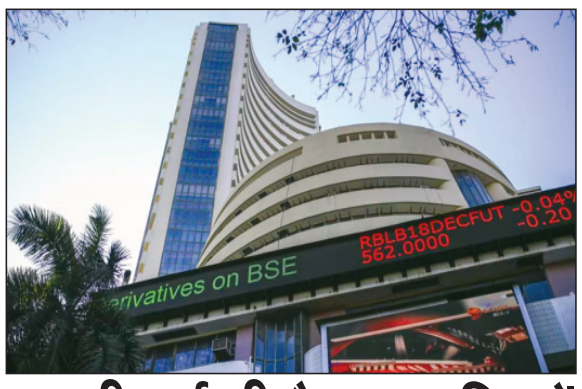

आरबीआई की बैठक पर निगाहें

863 अंक की सेंसेक्स में गिरावट

271 अंक निफ्टी टूटा

मुंबई, 3 अगस्त (वार्ता) अमेरिकी आयात शुल्क की चिंता में पिछले सप्ताह घरेलू शेयरों बाजारों में बिकवाली हावी रही और प्रमुख सूचकांक एक प्रतिशत से अधिक लुढ़क गये.

बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स पाँच में से दो दिन बढ़त के साथ बंद होने के बावजूद 863.18 अंक यानी 1.07 प्रतिशत की साप्ताहिक गिरावट के साथ शुक्रवार को 80,599.91 अंक पर बंद हुआ.

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी-50 भी सप्ताह के दौरान 271.65 अंक (1.09 प्रतिशत) टूटकर 24,565.35 अंक पर आ गया.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त आयात शुल्क लगाने की घोषणा के बाद दोनों प्रमुख सूचकांक लगातार पाँचवीं बार साप्ताहिक गिरावट में बंद हुये हैं. आने वाले सप्ताह में निवेशकों की नजर रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति बैठक पर होगी. तीन दिन की बैठक के बाद बुधवार को बयान जारी किया जायेगा.

इसके अलावा अडाणी पोर्ट्स, भारती एयरटेल, ट्रेंट, टाइटन और टाटा मोटर्स जैसी दिग्गज कंपनियों के तिमाही परिणाम भी सप्ताह के दौरान आने वाले हैं.

बीते सप्ताह ज्यादा शेयरों पर आधारित सूचकांकों में एनएसई के निफ्टी-100 में 292 .50 अंक (1 .15 प्रतिशत) की गिरावट रही और यह 25,149 .60 अंक पर बंद हुआ. मझौली और छोटी कंपनियों पर दबाव अधिक रहा. निफ्टी मिडकैप-50 में 2 .27 प्रतिशत और निफ्टी स्मॉलकैप-100 में 3 .42 प्रतिशत की गिरावट रही. वेंचुरा के अध्यक्ष एवं टेकनिकल हेड भरत के .गाला ने कहा कि निफ्टी-50 में अभी और गिरावट की संभावना है. यदि यह 24,375 अंक से भी नीचे उतरता है तो 24,165 अंक पर इसे समर्थन मिलना चाहिये. उससे नीचे उतरने पर 23,705 अंक पर इसमें लिवाली शुरू हो सकती है.

भारतीय सामान-हमारा स्वाभिमान अभियान शुरू

10 अगस्त से कैट चलाएगा राष्ट्रव्यापी स्वदेशी अभियान

प्रधानमंत्री की अपील को कैट का समर्थन

नयी दिल्ली, 03 अगस्त (वार्ता) कन्फ़ेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'भारतीय सामान खरीदो और बेचो' की अपील को समर्थन देते हुए घोषणा की है कि 10 अगस्त से इस संबंध में राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जाएगा जिसका उद्देश्य स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देना है.

यहां आयोजित कैट के दो दिवसीय राष्ट्रीय व्यापारी सम्मेलन में रविवार को यह निर्णय लिया गया. इस सम्मेलन में देश के 26 राज्यों के 150 से अधिक व्यापारी नेताओं ने भाग लिया. कैट के राष्ट्रीय महामंत्री एवं चांदनी चौक से सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने बताया कि सभी व्यापारी नेताओं ने एक स्वर से श्री मोदी के आह्वान को भारत की अस्मिता का प्रतीक बताते हुए इस अभियान का नाम 'भारतीय सामान - हमारा स्वाभिमान' रखने का निर्णय लिया है और कहा है कि प्रधानमंत्री की यह अपील आत्मनिर्भर भारत की भावना को सशक्त करती है.

उन्होंने कहा, विदेशी कंपनियों की एकाधिकारवादी नीतियों से बचकर यदि हम अपने देश के उत्पादों को बढ़ावा देंगे, तो इससे न केवल हमारा व्यापार मजबूत होगा बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था और रोजगार भी सशक्त होंगे.

उन्होंने कहा कि विदेशी कंपनियों की अनुचित व्यापार नीतियों से छोटे व्यापारी प्रभावित हो रहे हैं. भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता आज विश्वस्तरीय है और कीमत भी उचित है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील से भारतीय उत्पादों की खरीद से स्थानीय कारीगरों, उद्यमियों और व्यापारियों को समर्थन मिलेगा. विदेशी वस्तुओं की अंधाधुंध खपत से भारत का व्यापार घाटा बढ़ता है जिसको रोकना जरूरी है.

स्वर्ण उद्योग में मानकीकरण को मिलेगा नया आयाम

एमओयू बाबा साहेब अंबेडकर के दृष्टिकोण को करता है साकार

वैश्विक मानकों से मेल खाएगा भारतीय स्वर्ण उद्योग

नई दिल्ली, 3 अगस्त (वार्ता) भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) ने स्वर्ण उद्योग में वैल्यू चेन भागीदारों के लिए एक मजबूत एक्रेडिटेशन ढांचे को लागू करने के लिए इंडियन एसोसिएशन ऑफ गोल्ड एक्सीलेंस एंड स्टैंडर्ड्स (आईएजीईएस) के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं.

देश भर में स्वर्ण उद्योग के वैल्यू चेन में छह लाख भागीदारों के शामिल होने का अनुमान है.

विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की मौजूदगी में आईसीएआई के अध्यक्ष चरणजोत सिंह नंदा और आईएजीईएस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौशलेंद्र सिन्हा ने एमओयू का आदान-प्रदान किया.

श्री मेघवाल ने स्वर्ण उद्योग में मानकीकरण के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि देश में इसकी परिकल्पना सबसे पहले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने की थी. उन्होंने सोने के लिए एक विनियमित ढाँचे की वकालत की थी.

चावल-गेहूं के दामों में तेजी

नई दिल्ली, 3 अगस्त. घरेलू थोक जिंस बाजारों में बीते सप्ताह अनाज और चीनी-गुड़ की कीमतों में तेजी दर्ज की गई, जबकि दालों और खाद्य तेलों में मिला-जुला रुख देखने को मिला.

सरकारी वेबसाइट पर जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, चावल और गेहूं के औसत थोक भाव में बढ़ोतरी हुई है, जिससे इन प्रमुख खाद्यान्नों के दाम बढ़ गए हैं.

बीते सप्ताह चावल की औसत कीमत नौ रुपये बढ़कर 3,805.37 रुपये प्रति क्विंटल हो गई. इसी तरह, गेहूं भी नौ रुपये महंगा होकर 2,839.49 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर बिका. आटे की कीमत में भी 18 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई. इसके अलावा, गुड़ के औसत भाव 48 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ गए, जबकि चीनी भी चार रुपये प्रति क्विंटल महंगी हुई.

गुड़-चीनी के दाम चढ़े, तुअर-उड़द दाल हुई सस्ती

सरसों तेल में रु. 260 और मूंगफली तेल में रु. 99 की तेजी

जुलाई में एफपीआई ने खींचे 5,538 करोड़ रुपये

मुंबई, 3 अगस्त (वार्ता) विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने जुलाई में भारतीय पूँजी बाजार से शुद्ध रूप से 5,538 करोड़ रुपये (63.4 करोड़ डॉलर) की पूंजी की निकासी की. वैश्विक अनिश्चिताओं के बढ़ने के बीच यह लगातार दूसरा महीना है जबकि एफपीआई भारतीय पूँजी बाजार में शुद्ध रूप से बिकवाल रहे. जून में उनकी ओर से शुद्ध रूप से 63.4 करोड़ डॉलर की निकासी की गयी थी. जुलाई के पहले तीन सप्ताह में शुद्ध रूप से लिवाल रहे विदेशी निवेशकों ने आखिरी सप्ताह में जमकर बिकवाली शुरू कर दी थी.

बीएसएनएल-एनआरएल ने मिलाया हाथ

भारत की पहली रिफाइनरी में बनेगा 5G कैप्टिव नेटवर्क

गुवाहाटी, 3 अगस्त. भारत के डिजिटल परिवर्तन और औद्योगिक आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल) ने एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं.

इस समझौते के तहत, दोनों कंपनियां रिफाइनरी क्षेत्र में भारत का पहला 5जी कैप्टिव नॉन-पब्लिक नेटवर्क (सीएनपीएन) स्थापित करने के लिए मिलकर काम करेंगी.

इस पहल को औद्योगिक कनेक्टिविटी के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत माना जा रहा है, जो अत्यंत सुरक्षित, विश्वसनीय और रियल-टाइम कनेक्टिविटी प्रदान करेगा. संचार मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, यह कदम मिशन-क्रिटिकल कार्यों के लिए स्वदेशी 5जी तकनीक का लाभ उठाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है. बीएसएनएल और एनआरएल की यह साझेदारी अन्य औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भी एक अनुकरणीय मॉडल के रूप में काम करेगी, जिससे केंद्र सरकार के %आत्मनिर्भर भारत% के दृष्टिकोण को बल मिलेगा.

समाचार विशेष

दिल्ली से बिहार जीतने की रणनीति पर भाजपा सक्रिय

नई दिल्ली. बिहार विधानसभा चुनाव साल के अंत में हैं लेकिन इसकी बिसात अभी से बिछ गई है. राजधानी पटना से हजार किलोमीटर दूर देश की राजधानी दिल्ली में भी इसके लिए सियासी पार्टियों में गुणा-भाग शुरू हो गया है. इसकी बड़ी वजह दिल्ली में पूर्वांचल की बड़ी संख्या में आबादी का निवास करना है. यही वजह है कि भाजपा ने दिल्ली की गलियों से बिहार में चुनाव जीतने की इबारत लिखनी शुरू कर दी है.

प्रदेश भाजपा ने दिल्ली में बसे करीब 25 लाख पूर्वांचलियों को चुनावी रणनीति का केंद्रीय हिस्सा बनाया है. मिशन बिहार के तहत उसने दिल्ली के पूर्वांचली बहुल इलाकों में अपने नेताओं का प्रवास कराना शुरू कर दिया है. इस दौरान एक-एक व्यक्ति से संवाद कर, उनके गांव और परिजनों की जानकारी जुटाई जा रही है. लिहाजा इस बार भाजपा का फोकस सिर्फ बिहार में रैली या पोस्टर तक सीमित नहीं है, बल्कि दिल्ली से सामाजिक-सांस्कृतिक रिश्तों के माध्यम से बिहार में सियासी संदेश पहुंचाने की रणनीति तैयार की गई है. प्रदेश भाजपा ने अपने पूर्वांचल मोर्चा को विशेष जिम्मेदारी सौंपी है.

बिछी बिसात.. सियासी पार्टियों में गुणा-भाग शुरू

पूर्वांचल मोर्चा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी के अनुसार, पार्टी कार्यकर्ता परिवारों से मिलकर यह जानकारी ले रहे हैं कि वे बिहार के किस जिले, कस्बे और गांव से हैं. इसके साथ ही बिहार में रह रहे उनके माता-पिता, भाई-बहन, चाचा-मामा आदि का मोबाइल नंबर, गांव का नाम और पंचायत की जानकारी भी इकट्ठा की जा रही है.

यह जानकारी एकत्र करने के बाद भाजपा का आईटी सेल और डाटा टीम के जरिए एक मजबूत कॉल-सेंटर नेटवर्क तैयार किया जा रहा है. यह टीम गांव में रह रहे लोगों से सीधा संपर्क करेगी और भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेगी.

इस अभियान में भावनात्मक अपील भी शामिल है. दिल्ली में आपके अपने सुरक्षित हैं, क्योंकि दिल्ली में भाजपा है, बिहार में भी यही भरोसा बनना चाहिए. पूर्वांचल मोर्चा के पदाधिकारियों का कहना है कि यह महज एक चुनावी योजना नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और भावनात्मक पुल बनाने की कोशिश है. पार्टी के बड़े नेताओं खासकर सांसद मनोज तिवारी आदि को भी इन क्षेत्रों में भेजा जा रहा है.

भाजपा की सियासत

प्रदेश पूर्वांचल मोर्चा के पदाधिकारियों का कहना है कि दिल्ली में रहने वाला बिहार का एक निवासी अपने गांव में कम से कम पांच से 10 लोगों को राजनीतिक रूप से प्रभावित करता है. इसी आधार पर पार्टी ने हर परिवार, एक पोलिंग बूथ का आंतरिक नारा दिया है. इस अभियान के तहत पूर्वांचल मोर्चा के कार्यकर्ता उन इलाकों में प्रवास कर रहे हैं जहां बिहार से आए परिवारों की बड़ी आबादी रहती है. वह खास तौर पर संगम विहार, करावल नगर, बदरपुर, लक्ष्मी नगर, पालम, बवाना, किराड़ी, बुराड़ी, विकासपुरी, द्वारका आदि विधानसभा क्षेत्र में अधिक सक्रिय हैं.

भाजपा के नक्शेकदम पर नीतीश

जदयू के इन विधायकों का कटेगा टिकट!

पटना. बिहार विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया है. नीतीश कुमार सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए हर संभव तैयारी में जुटे हैं, जिसके लिए काफी सोच-समझकर कदम उठाए जा रहे हैं. अगर भाजपा और जदयू टिकट बंटवारे में 70 प्लस के फॉर्मूले पर वीटो लगाती है, तो मौजूदा 9 विधायकों के चुनाव लड़ने पर ग्रहण लग सकता है.

भाजपा और जदयू इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के चयन में आयु सीमा की नीति लागू कर सकती है. भाजपा पहले से ही यह दांव आजमाती रही है. भाजपा सत्तर की उम्र पार कर चुके नेताओं को मैदान में उतारने से बचती रही है. ऐसे में भाजपा पुराने चेहरों की जगह युवा नेताओं को मैदान में उतारकर नया नेतृत्व तैयार करने की रणनीति अपनाती रही है. ऐसा माना जा रहा है कि जदयू भी इस बार भाजपा के नक्शेकदम पर आगे बढ़ सकती है. बिहार विधानसभा में भाजपा और जदयू के कई बुजुर्ग विधायक हैं, जिनमें

से कुछ 80 तो कुछ 75 की उम्र पार कर चुके हैं. एनडीए के 9 विधायक ऐसे हैं, जो 70 की उम्र पार कर चुके हैं, जिनमें से छह जदयू के और तीन भाजपा के हैं. अगर भाजपा और जदयू आयु सीमा नीति कार्ड खेलते हैं, तो उनके लिए 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाएगा.

एनडीए के 70 प्लस विधायक

सुपौल से जदयू विधायक बिजेंद्र प्रसाद यादव वर्तमान विधानसभा में सबसे बुजुर्ग विधायक हैं. बिजेंद्र यादव 80 साल पार करने वाले हैं. सुल्तानगंज से जदयू विधायक ललित नारायण मंडल 75 साल के हो रहे हैं. बहादुरपुर से जदयू विधायक मदन सहनी की उम्र करीब 73 साल है.

क्या भाजपा-जदयू लगाएंगे उम्र की सीमा?

बिहार विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों ने अपने सिपहसालार उतारने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके लिए सीटवार सर्वे भी कराए जा रहे हैं. ऐसे में भाजपा और जदयू दोनों ने इस बार काफी सोच-समझकर उम्मीदवारों का चयन करने की योजना बनाई है. उम्र की सीमा और पार्टी की रणनीति में फिट नहीं बैठने वाले विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं. इस सूची में जदयू को बिजेंद्र प्रसाद और ललित नारायण जैसे अपने दिग्गज नेताओं के टिकट भी काटने पड़ सकते हैं.

राजद में 10 फीसदी सवर्ण कोटा!

पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 53 सदस्य

पटना. राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक लालू प्रसाद फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए तो उन्होंने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को नया रूप दिया है. पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 53 सदस्य रखे गए हैं, जिनमें उन्होंने पहले से मौजूद परिवार के सदस्यों में से बेटे तेज प्रताप यादव को निकाल दिया गया है और बेटी रोहिणी आचार्य को शामिल किया गया है. इन 53 सदस्यों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लालू प्रसाद ने पांच सवर्णों को जगह दी है. यह आंकड़ा 10 फीसदी से कुछ कम का है. ध्यान रहे बिहार में जाति गणना के आंकड़ों के मुताबिक हिंदू सवर्णों की आबादी 10 फीसदी है.

तभी सवाल उठ रहा है कि क्या राजद ने हिंदू सवर्णों के लिए 10 फीसदी का कोटा तय किया है? क्या उनका गठबंधन विधानसभा चुनाव में भी 10 फीसदी टिकट देगा? अगर 10 फीसदी टिकट दे तो इसका मतलब है कि 24 सवर्ण महागठबंधन से लड़ेंगे. हालांकि कई जानकारों का कहना है कि कांग्रेस की वजह से यह संख्या बढ़ सकती है. बहरहाल, लालू प्रसाद ने जिन सवर्ण नेताओं को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया है उनमें शिवानंद तिवारी के बेटे राहुल तिवारी भी हैं. उनके अलावा जगदानंद सिंह के बेटे और बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह को भी रखा गया है.

विशेष | **निकाय चुनाव में अपनी साख बचाने के लिए कांग्रेस की नई रणनीति**

कांग्रेस का ओबीसी दांव, उम्मीदवारी देने को भी तैयार

नागपुर. विधानसभा चुनाव में करारी हार के सदमे से निकलने में कांग्रेस को काफी समय लग गया. प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने अपने पद से इस्तीफा तक दे दिया. उसके बाद नवनियुक्त हर्षवर्धन सपकाल को राज्य के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई.

अब उनके नेतृत्व में स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे जिसके लिए संगठन का पोस्टमार्टम करने के पूर्व उन्होंने राज्यभर के सभी जिलों का दौरा किया. नेताओं, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं का मन टटोला.

अब भाजपा की ओर डायवर्ट हुए ओबीसी समाज को अपने पाले में लाने के लिए उन्होंने दांव खेलना शुरू कर दिया है. हाल ही में जारी जम्बो कार्यकारिणी में उन्होंने 44 फीसदी नेतृत्व ओबीसी को दिया है.

कांग्रेस ने यह रणनीति पहले ही तय कर रखी थी जिसे मूर्तरूप देकर ओबीसी को भरोसा दिया गया है कि निकाय चुनावों में भी समाज को 40 फीसदी या उससे अधिक की उम्मीदवारी दी जाएगी.

नये-पुराने सभी को साधा

कई गुटों में बटी कांग्रेस को एकजुट करने के लिए सपकाल ने नये-पुराने सभी को साधने का कार्य अपनी कार्यकारिणी में किया है. विदर्भ ने हमेशा संकट के समय कांग्रेस को तारने का कार्य किया है, यह इतिहास रहा है. निकाय चुनावों में विदर्भ में अधिक से अधिक निकायों पर कब्जा जमाने की रणनीति पर उसने कार्य करना शुरू कर दिया है.